



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2000/अग्रहायण 17, 1922

No. 283]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2000/AGRAHAYANA 17, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध महानिदेशालय)

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2000

विषय: चीन जनवादी गणराज्य से जिक्र आक्साईड के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना ।

सं. 62/1/2000—डी जी ए डी.—मैसर्स ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज लि., बड़ौदा और मैसर्स डेमोशा कैमिकल्स लि., मुंबई ने घरेलू उद्योग की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निदिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से (जिसे इसमें संबद्ध देश कहा गया है) से जिक्र आक्साईड के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग की हैसियत

यह याचिका मैसर्स ट्रांसपैक इंडस्ट्रीज लि. तथा मै. डेमोशा कैमिकल्स लि. द्वारा दायर की गई है जिनका पंजीकृत कार्यालय क्रमशः कालाली रोड, एटलाडरा रोड, वडोदरा, गुजरात और 105 ए, मित्तल टावर्स, 210, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400021 है । याचिकाकर्ता देश में जिक्र आक्साईड के घरेलू उत्पादन के बहुत बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं । अतः याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग की ओर से नियम 5(क) और (ख) तथा नियम 2(ख) के अनुसार याचिका दायर करने की हैसियत रखते हैं ।

3. शामिल उत्पाद

वर्तमान याचिका में शामिल उत्पाद संबंधित देश के मूल का अथवा वहां से निर्यातित जिक आक्साइड है (जिसे इसके पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उपशीर्ष 2817.0001 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से वर्तमान जांच के क्षेत्र में बाध्यकर नहीं है।

4. संबंधित देश

याचिकाकर्ता ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से जिक आक्साइड के पाटन का आरोप लगाया है।

5. समान वस्तुएं

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसके द्वारा उत्पादित माल तथा सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2817.0001 के तहत वर्गीकृत वस्तु का कोई प्रतिस्थापन नहीं है तथा चीन जनवादी गणराज्य से आयातित वस्तु के साथ तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। अतः इसे नियमों के अर्थों के भीतर संबद्ध देशों से आयातित समान वस्तु माना जाना चाहिए।

6. सामान्य मूल्य

सामान्य मूल्य का उल्लेख उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया गया है और संबद्ध देश के लिए उचित समायोजनों की अनुमति दी गई है।

7. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने द्वितीय स्रोतों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है जो भारत को संबद्ध माल की निर्यात कीमत की सूचना प्रदान करते हैं। इस सूचना का मिलान डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से भी किया गया है और संबद्ध देश में संबद्ध माल की कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत आंकने के लिए उचित समायोजनों पर भी विचार किया गया है।

8. डरपिंग मार्जिन

इस बात के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों का सामान्य मूल्य उस मूल्य से बहुत अधिक है जिस पर इसे भारत को निर्यात किया गया है। इस बात से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि निर्यात को द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति

क्षति के संबंध में विभिन्न मापदंडों जैसे पाटित वस्तुओं से कीमतों में कमी आना, स्थिर मांग के बावजूद कम कीमतों के कारण वित्तीय हानि होना आदि से प्रथम दृष्टया सामूहिक एवं संचयी रूप से यह संकेत मिलते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

10. पाटनरोधी जांच शुरू करना

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की कथित डपिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हैं।

11. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1.4.99 से 30.9.2000 तक की है।

12. सूचना प्रस्तुत करना

उक्त देशों के निर्यातकों और भारत में ज्ञात आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे अपने विचार तथा संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकते हैं:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

13. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी

14. सभी हितबद्ध पक्षों को चाहिए कि वे पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर दी गई किसी भी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें। तथापि, यह बात नोट की जाए कि यह सूचना नियम 7(1) और (2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण निर्धारित समय सीमाओं के समाप्त होने के बाद कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

16. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिश कर सकता है।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2000

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Zinc Oxide from Peoples Republic of China

No. 62/1/2000-DGAD.—M/s. Transpek Industries Ltd., Baroda and M/s. Demosha Chemicals Limited Mumbai have filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Zinc Oxide from PR China (herein referred to as subject country) and have requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping duties.

2. **Domestic industry standing:** The petition has been filed by M/s Transpek Industries Ltd. and M/s Demosha Chemicals Ltd. having registered offices at Kalali Road, Atladra Road, Vadodara, Gujarat and 105A, Mittal Towers, 210, Nariman Point, Mumbai-400021 respectively. The petitioners account for a major proportion of the domestic production of Zinc Oxide in the country. Therefore, the petitioners satisfy the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) and Rule 2 (b).
3. **Product involved:** The product involved in the present investigation is Zinc Oxide (herein referred to as subject goods), originating in or exported from the subject country and classified under Customs Sub-heading 2817.0001 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
4. **Countries involved:** The petitioner has alleged dumping of Zinc Oxide from PR China (herein referred to as subject country).
5. **Like articles:** The petitioner has claimed that the goods produced by them and are classified by Custom Tariff under head 2817.0001 have no substitute and are technically and commercially substitutable with the goods imported from PR China and, therefore, be treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules.

6. **Normal value:** The normal value has been referenced on the basis of the constructed cost of production with appropriate adjustments for the subject country.
7. **Export Price:** The petitioner has claimed Export price based on secondary sources, which provide information on export price of subject goods to India. The same has been reconciled with the data provided by DGCI&S and also appropriate adjustments have been considered to evaluate the ex-factory export price of the subject goods in the subject country.
8. **Dumping margin:** There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.
9. **Injury:** Various parameters relating to injury such as price undercutting by dumped imports, financial losses due to depressed prices despite stable demand, prima-facie collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping from subject country.
10. **Initiation of Anti-Dumping investigation:** The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
11. **Period of investigation:** The period of investigation for the purpose of present investigation is 1.4.99 to 30.9.2000.
12. **Submission of information:** The exporters in the said country and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

13. **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known

3345 G/2000-2

- exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.
14. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2). Please, however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).
 15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties after expiry of time limits set.
 16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

L.V. SAPTHARISHI, Designated Authority